भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 291

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

भारत चावल

291. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत आटा, भारत दाल आदि की तर्ज पर भारत चावल बेचना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में भारत चावल बेचना शुरू करेगी;

(घ) क्या भारत चावल को केवल भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव है; और

(ड.) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से भारत चावल बेचने पर भी विचार कर रही है ताकि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को लाभ मिल सके?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड.): जी हाँ। खाद्य अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई महंगाई की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, दिनांक 6 फरवरी, 2024 को भारत चावल की खुदरा बिक्री की शुरुआत सब्सिडीयुक्त दरों पर बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए की गई है। आंध्र प्रदेश सहित देशभर में भारत चावल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), जो 29/- रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से अधिक न हो, पर बेचा जा रहा है। इन संगठनों द्वारा अपने स्थायी खुदरा आउट्लेट्स, मोबाइल वैन के अलावा अन्य खुदरा नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ इन संगठनों के गठजोड़ के माध्यम से भारत चावल बेचा जाता है।

******